

कोरोना के नाम पर मॉक ड्रिल की नौटंकी डीसी ने किया ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण

फरीदाबाद (म.मो.) कोरोना की एक बड़ी लहर आने की आशंका के प्रति सरकारी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने के लिये देश भर के अस्पतालों की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस सम्भावित बीमारी से निपटने के लिये मोदी सरकार तरह-तरह के कार्डों एवं बीमों के साथ अस्पतालों की क्षमता परखने का नाटक करवा रही है।

इसी नीति के तहत उपायुक्त विक्रम ने दिनांक 27 दिसंबर को उस ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया जिसकी दक्षता एवं कार्यकुशलता भली-भांति परखी हुई है। बीती दो कोरोना लहरों का सबसे बेहतरीन मुकाबला किसी ने किया था तो वह यही अस्पताल है। जांच-पड़ताल करने की कहीं कोई आवश्यकता है तो वे हीं राज्य सरकार द्वारा संचालित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल छांयसा, बीके अस्पताल तथा ईएसआई अस्पताल सेक्टर आठ। इन अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। बीती दोनों भयंकर लहरों के बावजूद इनकी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा।

एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 800 बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। इनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिये 10 हजार लीटर तरल ऑक्सीजन के भंडार के साथ-



साथ 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का प्लांट भी बेहतरीन हालत में है। संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि प्लांट द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की अपेक्षा भंडारण की गई तरल ऑक्सीजन कहीं ज्यादा बेहतरीन एवं उत्तम क्वालिटी की होती है। प्लांट द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब तरल उपलब्ध न हो रही हो। कोरोना मरीजों के मामले में सबसे अधिक आवश्यकता इसी ऑक्सीजन की पड़ती है।

समझा जाता है कि इस अस्पताल का निरीक्षण करके डीसी विक्रम पूरी तरह से

संतुष्ट एवं प्रसन्न हो गये। लेकिन लगे हाथ उन्हें यह भी समझ लेना चाहिये कि यह सरकारी अस्पताल नहीं है। इसमें न तो राज्य सरकार का और न ही केंद्र सरकार का कोई पैसा लगा हुआ है। यह पूर्णतया मजदूरों वसूल गले गये पैसे से बना है और चलाया जा रहा है। इसके लिये उनके वेतन से प्रति माह चार प्रतिशत काट लिया जाता है। इस लिये डीसी साहब को इस मुगालते में कर्तव्य नहीं रहना चाहिये कि कोरोना महामारी के समय वे इसे अपने नियंत्रण में ठीक वैसे ही ले लेंगे जैसे कि बीती दो लहरों में ले लिया गया था। उस वक्त उन गरीब मजदूरों के लिये इसे पूर्णतया बंद करके जिला प्रशासन ने कब्जा लिया था, जिनके पैसे से यह चल रहा है।

फिलहाल यहां साढे चार हजार मरीज ओपीडी में आते हैं और 800 से अधिक मरीज विभिन्न बार्डों में भर्ती रहते हैं। उस वक्त इनके लिये ओपीडी पूर्णतया बंद कर दी गई थी और भर्ती मरीजों को भगा दिया गया था। लेकिन इस बार तमाम मजदूर संगठनों ने कड़ा निर्णय ले लिया है कि वे इस प्रशासनिक गुंडागर्दी को सहन करने वाले नहीं हैं। जिस दिन शासन-प्रशासन ने गत वर्षों वाली गुंडागर्दी दोहराने के लिये मजदूरों को अस्पताल से खदेड़ने का प्रयास किया तो वे इसे सहन नहीं करेंगे और जमकर प्रशासन को इसका जवाब देंगे।

अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल 'दो दिन में चल जायेगा' का फर्जी दावा



छांयसा के गांव मोटूका में गोल्ड फॉल्ड नामक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीते करीब चार साल से हरियाणा सरकार के कब्जे में है। ये पूर्णतया बना-बनाया व चालू प्राइवेट कॉलेज व अस्पताल था। इसके फेल हो जाने पर सरकार ने बैंकों का करोब 129 करोड़ अदा करके इसे अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन इसे चलाने की जरूरत कभी नहीं समझी।

बीती कोरोना लहरों के दौरान जब 'मजदूर मोर्चा' ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बजाय उक्त अटल बिहारी अस्पताल न चलाने को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर पर सवाल किया तो उन्होंने तुरन्त (25 अप्रैल 2021) जवाब दिया था कि वे इसे दो दिन में चालू कर देंगे। उन बातों को अब दो साल होने को हैं। इसके बावजूद आज भी वहां का हाल निल बटा सन्नाटा ही है। आज भी वहां न तो कोई ओपीडी है और न ही कोई वार्ड में भर्ती है। ऑक्सीजन नाम की कोई वस्तु वहां नहीं है। और तो और साधारण डिलिवरी तथा आपातकालीन चिकित्सा तक की कोई व्यवस्था है।

हां, जनता को बहकाने में माहिर खट्टर सरकार ने वहां तरह-तरह के पाखंड जरूर किये थे। इसे फौज द्वारा चलाने का नाटक भी खेला गया था। तमाम स्थानीय भाजपा विधायकों, संसद एवं मंत्रियों आदि ने वहां हवन-यज्ञ आदि भी किये थे। कुछ दिन के लिये वहां फौजी अफसरों को भी घमते देखा गया था। लेकिन आज वहां बेशक 100 छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई कराने के नाम पर भर्ती तो कर लिया गया है, लेकिन वहां है कुछ भी नहीं। डीसी साहब वहां का निरीक्षण करके खट्टर को क्यों नहीं बताते कि यहां पर सही इंतजाम किया जाय तो पांच-सात सौ कोरोना मरीजों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन खट्टर अफसरों की सलाह मानने की अपेक्षा उल्टे-सीधे आदेश देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं।

गौरतलब है कि एनएच तीन स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा बीके अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में तो 140 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी चल रही है यानी कि 100 बेड पर 140 मरीज भर्ती हैं। इनके लिये जरूरत से आधा भी स्टाफ उपलब्ध नहीं है। जाहिर है कि कोरोना अथवा अन्य कोई महामारी की स्थिति में अतिरिक्त बेड की आवश्यकता होती है। ऐसे में पहले से ही भर्ती मरीज कहां जायेंगे? यदि सरकार की नीयत सही है तो वह इस तरह के मॉक ड्रिल के नाटक करने के बजाय, समय रहते अपने ही अस्पतालों में अतिरिक्त बेड व स्टाफ का इंतजाम करे।

सेक्टर आठ का बीमार ईएसआई अस्पताल

200 बेड के इस अस्पताल का नियंत्रण एवं संचालन पूरी तरह से हरियाणा सरकार के पास है। यद्यपि इसके सारे खर्च का मात्र आठवां भाग ही राज्य सरकार खर्च करती है, शेष सात भाग ईएसआई कार्पोरेशन खर्च करती है। इसके बावजूद यह अस्पताल 200 की बजाय केवल 50 बेड ही चला रहा है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 50 बेड में से भी बमुश्किल 20-25 बेड पर ही मरीज दाखिल रहते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, न तो यहां पर्याप्त डॉक्टर व अन्य स्टाफ हैं और न ही दवायें एवं उपकरण उपकरण आदि।

यदि सरकार की नीयत ठीक होती और कोरोना काल की भीषण परिस्थितियों से कोई सबक लिया होता तो यहां के भी 200 बेड चालू हो गये होते। तरल ऑक्सीजन भंडारण की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य तमाम कार्मियां भी दूर कर ली गई होती। मजे की तो बात यह है कि ईएसआई कार्पोरेशन के पास मजदूरों द्वारा दिये गये पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन नीयत न तो हरियाणा सरकार की ठीक है और न ही कार्पोरेशन की। दोनों का ही जनहित से कोई लेना-देना नहीं।



अस्पताल में साधारण हालात में ही मरीजों से निपटने की पर्याप्त क्षमता न हो तो वह पायेगा? बेहतर होता यदि डीसी साहब इस अस्पताल के सुधार बाबत कोई कदम उठाने का प्रयास करते।